

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38, सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2005—कार्तिक 13, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-1-17/2005/एक/2.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से. (1972) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग एवं कृषि उत्पादन आयुक्त को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए अन्तर मुख्य सचिव, कृषि विभाग के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है. वे अपने कार्य के साथ-साथ कृषि उत्पादन आयुक्त का कार्य भी संपादित करेंगे.

2. श्री व्ही. के. कपूर, भा. प्र. से. (1972) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए महानिदेशक, प्रशासन अकादमी के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है। साथ ही उन्हें अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है।
3. श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से. (1973) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, खनिज साधन, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज निगम तथा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम खनिज साधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज निगम तथा अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।
4. श्री बी. के. एस. रे एवं श्री शिवराज सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-1954 के नियम 9 (1) के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 3(ए) में सम्मिलित मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है।
5. श्री व्ही. के. कपूर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-1954 के नियम 9 (1) के अंतर्गत महानिदेशक, प्रशासन अकादमी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 3(ए) में सम्मिलित मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव।

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ. 7-16/2005/1/6.—राज्य शासन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 द्वारा गठित "छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग" के लिए निम्नानुसार राजपत्रित अधिकारियों के पदों का निर्माण किया जाता है :-

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	1	30000/-
2.	सूचना आयुक्त	1	26000/-
3.	सचिव	1	18400-22400

2. इस हेतु वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 1209/बजट-5/वित्त/4 दिनांक 14-10-2005 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव।

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-7/36/2004/1/2.—श्री सुजत साहू, भा.प्र.से. तत्का. पंजीयक, सहकारी संस्थान, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 16-8-2005 से 9-9-2005 तक (25 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 10 एवं 11-9-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. अवकाश काल में श्री साहु, भा.प्र.से. को अवकाश बेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहु, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक/1130/पं./22.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 65 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत (स्थावर सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 4 में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" स्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक पत्राविवि/2005/1129.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में संशोधन बाबत अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th October 2005

No./1130/P/22.—In exercise of the power conferred by the sub-section (1) of section 95 read with sub-section (2) of section 65 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Panchayat (Transfer of immovable property) rules, 1994 the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section 95 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In rule 4 in place of the words "three years" the words "five years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY GARG, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक/1132/प./22.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 46 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थाई समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) में शब्द "भूमि विकास तथा संरक्षण, राजस्व, बीस सूत्रीय कार्यक्रम" का लोप किया जाए.
2. नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ख) में शब्द "वन", "डेयरी", "कृषि तथा जल संसाधन" का लोप किया जाए.
3. नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) में शब्द "मत्स्यपालन" तथा "श्रम" का लोप किया जाए.
4. नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए :—

"(घ) कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन समिति-ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि, भूमि विकास तथा संरक्षण, उन्नत बीज, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्यपालन, लघु सिंचाई तथा श्रम.

(ङ) राजस्व तथा वन समिति-ग्राम पंचायत क्षेत्र में राजस्व, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, वन, सामाजिक वानिकी, उद्यान, लघु वनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रम."

5. नियम 3 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु कोई समिति अधिक से अधिक दो ऐसे व्यक्ति को सहयोजित कर सकेगी जिन्हें उस समिति को सौंपे गये विषयों का अनुभव या विशेष ज्ञान हो. इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को समिति की कार्यवाहियों में मत देने का अधिकार नहीं होगा.

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत जब और जैसे भी आवश्यक हो, बैठक में शासकीय अधिकारियों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों को सलाह लेने के लिये आमंत्रित कर सकेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक पत्राविवि/2005/1131.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में संशोधन वावत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th October 2005

No./1132/P/22.—In exercise of the power conferred by the sub-section (1) of section 95 read with sub-section (3) of section 46 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Term of office of members of standing committee and procedure for the conduct of Business) rules, 1994, the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section 95 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In clause (a) of sub rule (1) of rule 3 the words "Land development and protection", "Revenue", "20 point programme" shall be omitted.
2. In clause (b) of sub rule (1) of rule 3 the words "Forest", "Dairy", "Agriculture" and "Irrigation" shall be omitted.
3. In clause (c) of sub rule (1) of rule 3 the words "Fishery" and "Labour" shall be omitted.
4. After clause (c) of sub rule (1) of rule 3 the following clauses (d) and (e) shall be inserted—

"(d) The committee on Agriculture, Animal husbandry and Fishery- Agriculture, Land development and conservation, Improved seeds, Horticulture, Dairy, Animal husbandry, Fishery, Small irrigation and Labour in gram panchayat area.

(e) The committee on Revenue and Forest-Revenue, 20 point programme, Forest, Social forestry, Horticulture, Development of small forest produce and other forestation programme."

5. After sub rule (2) of rule 3 the following proviso shall be inserted :—

"Provided that any committee may co-opt not more than two persons having subject experts or subject knowledge. Such co-opted persons shall not have voting right during the proceedings.

Provided further that the Gram Panchayat may summon Government officers and subject experts in the meeting to get advise as and when required."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
SANJAY GARG, Joint Secretary

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक 7699/एफ 1-28/05/स्था-1.—छत्तीसगढ़ अभियांत्रिकीय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1969 के नियम 15 (5) के अनुसार "कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए कार्यपालन अभियंता के पद पर सेवा अवधि कम से कम 5 वर्ष का प्रावधान है।"

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यपालन अभियंता की न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अर्हता की शर्त को सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये शिथिल करते हुए यह सेवा अवधि 3 वर्ष 9 माह करता है।

यह शिथिलीकरण वर्ष 2005 में होने वाली डी. पी. सी. के लिये, केवल एक बार के लिए प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. प्री. केशरी, सचिव।

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8163 /डी-2419/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 602/11-2-16/01/गोपनीय/05, दिनांक 4-10-05 के अनुपालन में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता फोरम में अध्यक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु सारणी में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, रायपुर को एतद्वारा सौंपी जाती है:—

क्रमांक	न्यायिक अधि. का नाम एवं पदनाम	अनुशंसित प्रतिनियुक्ति स्थान
1.	श्री राजेन्द्र चंद सिंह सामन्त, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव.	रायपुर
2.	श्री दिनेश कुमार तिवारी, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (जिला स्था.) छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव।

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-5-43/दो/आठ-परि/2005.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 14 की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

- (एक) नियम 11 के उप नियम (2) में शब्द “दस रुपये” के स्थान पर “रुपये पांच सौ” स्थापित किए जाएं.
- (दो) नियम 12 के उप नियम (2) में शब्द “दस रुपये” के स्थान पर “रुपये पांच सौ” स्थापित किए जाएं.

No. F-5-43/Two/Eight-Trans/2005.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Chhattisgarh Motoryan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Motoryan Karadhan Niyam 1991, namely:—

AMENDMENT

In the said rules :—

- (1) In sub rule (2) of rule 11, place of words "Rupees Ten" the word "Rupees Five hundred" shall be substituted.
- (2) In sub rule (2) of rule 12 in place of words "Rupees Ten" the word " Rupees Five hundred" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ ८-३/2005/11/6.—इंडियन वायलर्ड एल. १९७३ की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा भिलाई इस्तेमाल सप्लाय कम्पनी प्रा. लि. भिलाई (एन. टी. सी. व सेल का संयुक्त उद्यम) के वायलर्ड क्रमांक एम. पी./3520 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 14-10-2005 से दिनांक 13-12-2005 तक

की छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रख जावेगा.
5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-18/दो/गृह/05.—गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "पुलिस शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री राहुल शर्मा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री ओम प्रकाश पाल	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक/3380/बी-8/11/2005-06/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्र. 13011/15/99/क्रेडिट-II, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा "राज्य स्तरीय उप समिति" की बैठक दिनांक 22-9-2005 में की गई अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2005-06 मौसम के लिए संलग्न अनुसूची के अनुसार तहसीलों को उनके सम्मुख दर्शाई गई रबी फसल के लिये राज्य शासन एतद्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत रबी मौसम 2005-06 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्रमांक (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	परिभाषित तहसीलें (4)
1.	गेहूं सिंचित	रायपुर	1. रायपुर 2. तिल्दा 3. भाटापारा 4. आरंग 5. सिमगा 6. पलारी
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
		धमतरी	1. कुरूद
		दुर्ग	1. दुर्ग 2. पाटन 3. धमधा 4. बेमेतरा 5. बेरला 6. साजा 7. गुण्डरदेही 8. नवागढ़
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. पण्डरिया 2. कवर्धा
		बस्तर	1. जगदलपुर
		बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. कोटा 3. बिल्हा 4. मस्तुरी

(1)	(2)	(3)	(4)
			5. तखतपुर 6. पेण्डारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित) 7. मुंगेली
		जांजगीर-चांपा	1. मालखरीदा 2. जांजगीर
		रायगढ़	1. रायगढ़
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. राजपुर 3. लुण्डा 4. सीतापुर 5. सूरजपुर 6. प्रतापपुर 7. पाल 8. वाड्फनगर 9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. भरतपुर
		जशपुर	1. बगीचा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगांव 3. डोंगरगढ़
2.	गेहूं असिंचित	रायपुर	1. आरंग 2. पलारी
		धमतरी	1. कुरूद
		दुर्ग	1. दुर्ग 2. पाटन 3. गुण्डरदेही 4. धमधा 5. नेमेलरा 6. बेरला 7. नवागढ़ 8. साजा 9. बालोद

(1)	(2)	(3)	(4)
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान
		कबीरधाम	1. कंवर्धा 2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली 2. पेण्डारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित) 3. लोरमी 4. तखतपुर
		सरगुजा	1. सूरजपुर
3.	चना	रायपुर	1. रायपुर 2. आरंग 3. तिलदा 4. अभनपुर 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. पलारी
		धमतरी	1. धमतरी 2. कुरूद 3. नगरी
		दुर्ग	1. दुर्ग 2. पाटन 3. बालोद 4. धमधा 5. बेमेतरा 6. बेरला 7. नवागढ़ 8. साजा 9. गुरूर 10. गुण्डरदेही 11. डौण्डीलोहारा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
			2. डोंगरगढ़ 3. छुईखदान 4. खैरागढ़ 5. डोंगरगांव
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा 2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. तखतपुर 2. मुंगेली 3. लोरमी 4. पेण्डारोड (मरवाही सहित) 5. कोटा
		जशपुर नगर	1. पथलगांव
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. सूरजपुर
4.	अलसी	धमतरी	1. कुरूद 2. धमतरी 3. नगरी
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
		दुर्ग	1. गुरूर 2. पाटन 3. गुण्डरदेही 4. धमधा 5. बेमेतरा 6. बेरला 7. नवागढ़ 8. डौण्डीलोहारा 9. साजा 10. बालोद
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. छुईखदान 4. खैरागढ़ 5. डोंगरगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
			6. मोहला 7. अंवागढ़ चौकी
		कबीरधाम	1. कवर्धा 2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली 2. पेण्डारोड (भरवाही तहसील शामिल) 3. कोटा
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. चांपा
		कोरबा	1. करतला
		जशपुर नगर	1. पत्थलगांव
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. सीतापुर 3. राजपुर 4. सूरजपुर 5. प्रतापपुर 6. पाल (रामानुजगंज) 7. वाड्डफनगर 8. लुण्ड्रा
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
5.	राई सरसों	धमतरी	1. धमतरी 2. कुरुद
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा 2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव 3. नारायणपुर
		कांकेर	1. अंतागढ़
		दन्तेवाड़ा	1. दन्तेवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
		विलासपुर	1. पेण्डारोड (मरवाही तहसील शामिल) 2. कोटा
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
		कोरवा	1. कटघोरा
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
		जशपुर नगर	1. जशपुर 2. बगीचा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. राजपुर 3. लुण्ड्रा 4. सीतापुर 5. सूरजपुर 6. प्रतापपुर 7. पाल 8. वाड्डफनगर 9. सामरी
		कोरिया	1. सोनहत 2. मनेन्द्रगढ़ 3. भरतपुर 4. वैकुण्ठपुर
6.	आलू	सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. सीतापुर 3. सूरजपुर 4. पाल
		जशपुर	1. बगीचा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा./भू.वि.अ./प्र. क्र. 40-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	किरना प. ह. नं. 10	3.711	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	किरना वितरक नहर के किरना माइनर नं. (2) के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा./भू.वि.अ./प्र. क्र. 41-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	ग्राम जलसो प. ह. नं. 10	0.024	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	किरना वितरक शाखा नहर के किरना माइनर नं. (2) के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बनसिया प.ह.नं. 10	0.073	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) रायगढ़.	मिट्टुमुड़ा, सांगीतराई, ननसिया- बनसिया मार्ग में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 सितम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 8 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	अजिरमा	0.97	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) संभाग क्रमांक 1, अम्बिकापुर.	रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 सितम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 98 अ-82/1985-86.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	सलका	0.726	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) स. क्र.-1, अम्बिकापुर.	लटोरी चन्द्रमेढ़ा मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2005-06.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कोडेनार	0.96	अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2005-06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	तिरथम	3.13	अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/2005-06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	परपा	0.46	अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2005-06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	डिलमिली	4.07	अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/2005-06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	राजूर	1.68	अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/2005-06.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	काटाकांदा	2.84	अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/2005-06.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बास्तानार	14.25	अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बड़े किलेपाल	8.52	अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/9/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	रायकोट	4.53	अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशाली अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कोड़पाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.055 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
585/1	0.079
585/3	0.162
631/1	0.319
632	0.189
635	0.793
636/1	0.332
636/2	0.506
637	0.101
638/1	0.234
638/2	0.004
639/6	0.008
762	0.146
763	0.182
योग	13
	3.055

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोड़पाली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-कोनपारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.951 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
251/4	0.283
251/10	0.668
योग	2
	0.951

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है-सिंचाई विभाग द्वारा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		2/16	1.525
(क) जिला-रायगढ़		2/6	0.227
(ख) तहसील-रायगढ़		2/7	0.113
(ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 14		2/8	0.263
(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.491 हेक्टेयर		2/11	0.182
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	2/12	0.097
		15/1	0.400
(1)	(2)	24/1	0.206
		15/4	0.148
2/1	2.162	15/5	0.162
2/17	2.751	15/6	0.081
2/4	0.405	24/1	0.198
2/5	0.308	15/7	0.089
2/9	0.607	15/8	0.077
2/10	0.227	15/9	0.073
20	0.045	18/1	0.085
4/1	0.146	18/2	0.085
11/1	0.121	21/1	0.202
4/2	0.223	21/2 क	0.279
7	0.506	21/2 ख	0.279
15/2	0.198	25/2	0.210
11/2	0.142	12/3	0.148
11/4	0.150	41/1	0.458
14/1	0.008	41/2	0.073
16	0.053	41/5	0.269
14/2	0.206	41/3	0.129
25/1	0.214	19	0.045
14/3	0.316	31/1	0.081
29	0.324	22	0.279
30	0.142	36/1	1.870
15/3	0.081	10/1	0.429
4/3	0.210	11/3	0.121
10/3	0.401	2/13	0.202
28	8.345	2/13	0.227
35	0.789	41/6	0.269
12/1	0.149	41/4	0.129
12/2	0.149	41/7	0.028
2/14	0.109	41/8	0.022
2/15	0.125	37/2	0.854

(1)	(2)	(1)	(2)
37/8	0.943	31	0.077
12/4	0.149	48/1	0.053
		63/3	0.384
योग	71	42/1	0.656
	31.491	62	1.947
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोक-ओवन, ब्लास्ट फर्नेश एवं सिन्टर प्लांट हेतु भू-अर्जन.		52/5	0.032
		33	0.154
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.		44	0.263
		48/2	0.117
रायगढ़, दिनांक 25 अक्टूबर 2005		63/1	0.267
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		63/4	0.065
		63/5	0.113
		65/2	0.259
		23/3	0.049
		10/2	0.121
		10/3	0.101
		19/4	0.263
		21/2	0.109
		46/2	0.745
		64/2	0.321
		14/1	0.081
		65/1	0.263
		13/7	0.251
		3	0.348
		14/2	0.146
		23/1	0.413
		24/3	0.089
		24/1	0.142
		13/6	0.121
		13/8	0.138
		21/4	0.512
		13/1	0.193
		21/1	0.463
		46/1	0.372
		64/1	0.161
		13/2	0.025
		21/2	0.304
		13/9	0.247

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.549 हेक्टेयर -

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

7/3

0.032

7/1

0.138

7/4

0.032

7/6

0.129

7/5

0.032

7/7

0.064

32

0.134

34

0.162

5

0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
2/1 ख	0.271	51/1	0.364
10/1	0.182	99	0.081
		100	0.259
योग	49	77/2	0.073
	11.549	101/2	0.072
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोक-ओवन, ब्लास्ट फर्नेस एवं सिंटर प्लांट हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.		56/1	0.040
		53	0.251
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.		134/2	0.235
		134/6	0.105
		134/3	0.345
		134/7	0.470
		134/9	0.049
		52	0.445
रायगढ़, दिनांक 25 अक्टूबर 2005		90/2	0.263
		95	0.101
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		72/3	0.026
		36	0.312
		37/8	0.061
		34	0.251
		30	0.563
		90/1	0.575
		94/2	0.206
		31/1	0.020
		31/2	0.073
		107/1	0.069
		107/3	0.032
		109/3	0.113
		134/4	0.049
		111/1	0.093
		111/3	0.032
		111/4	0.036
		47/6	0.049
		55/10	0.028
		55/12	0.028
		55/11	0.024
		41/3	0.081
		68/2	0.154
		74/2	0.098
		70	0.081
		68/1	0.182
		74/1	0.170
		67/1	0.429
		71	0.551
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
94/1	0.749		
98/1	0.179		
50/1	0.118		
97/1	0.227		
98/2	0.101		
98/3	0.024		
98/4	0.182		
97/2	0.182		
50/2	0.109		

(1)	(2)	(1)	(2)
83	0.344	55/5	0.014
66/2	0.057	55/9	0.034
66/3	0.262	55/6	0.037
66/1	0.081	57/2	0.032
84	0.053	75	1.263
86	0.085	78/2	0.858
55/8	0.020	69/9	0.324
55/7	0.042	69/11	0.324
38/1	0.922	69/12	0.324
102	0.579	69/14	0.324
38/3	0.129	36/9	0.133
39/2	0.348	78/1	0.445
46	0.413	76	1.757
137	1.072	48/1	0.162
42/1	0.207	48/3	0.113
42/3	0.012	103	0.247
47/1	0.141	135	0.425
47/3	0.036	44/4	0.073
49/1	0.129	42/4	0.074
49/3	0.040	42/5	0.053
55/1	0.028	42/6	0.186
55/4	0.026		
44/3	0.012	योग	106
92/1	0.085		23.076
41/2	0.449		
47/7	0.141		
51/2	0.129		
51/3	0.061		
55/8	0.025		
92/2	0.049		
67/2	0.417		
47/4	0.042		
47/5	0.028		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोक-ओवन, ब्लास्ट फर्नेस एवं सिंटर प्लांट हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.